

संसद की बदली हुई बेंच स्ट्रेंथ से उम्मीदें बढ़ीं

द हिन्दू

पेपर- II (भारतीय राजव्यवस्था)

18वीं लोकसभा से बहुत उम्मीदें हैं, जिसका पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि नया सदन अपने कार्यकाल के दौरान अपने कामकाज और विचार-विमर्श में अलग होगा। यह उम्मीद सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कम संख्या और कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत के कारण है, जो पिछले दो लोकसभा संस्करणों के मुकाबले कम है।

एक दशक के अंतराल के बाद, सरकार एक गठबंधन है, जिसका नेतृत्व सबसे बड़ी पार्टी के नेता द्वारा किया जाता है, और अब यह दो क्षेत्रीय सहयोगियों, जनता दल (यूनाइटेड) और तेलुगु देशम पार्टी के महत्वपूर्ण समर्थन पर निर्भर है। हालाँकि, तकनीकी रूप से, भाजपा ने 2014-24 के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया, लेकिन तब स्थिति अलग थी क्योंकि प्रमुख पार्टी के पास बेंच स्ट्रेंथ में आराम था, जो वर्तमान में गायब है।

विपक्ष के लिए अधिक स्थान:

2024 में जनता द्वारा दिया गया फैसला स्पष्ट है। देश को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन की नीतियों और कार्यक्रमों के विपरीत विचार रख सके और प्रतिरोध का सामना किए बिना अपने एजेंडे को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने की अग्रणी पार्टी की क्षमता को कुंद कर सके। 18वीं लोकसभा के नए सदस्यों के शपथ लेने के साथ ही, संयुक्त विपक्षी ताकत 230 से थोड़ी अधिक है, जबकि 300 से अधिक सदस्यों वाला सत्तारूढ़ गठबंधन अपने पक्ष में तराजू को अनिश्चित रूप से झुकाता है।

नए सदन के गठन में यह बदलाव इस उम्मीद को जन्म देता है कि विपक्ष की चिंताओं के प्रति सरकार की ओर से अधिक समायोजन किया जाएगा। पिछले दशक के दौरान, सरकार का विरोध करने वाले सांसदों ने शिकायत की कि बहुमत की दीवार के पीछे, भाजपा के संसदीय प्रबंधकों ने बहुत कम जगह दी। इस दावे का समर्थन करने के लिए अक्सर जिन उदाहरणों का हवाला दिया जाता है, वे संसद में चीन के साथ खूनी झड़पों के बाद सीमा की स्थिति और उससे जुड़े मुद्दों पर स्थगन या चर्चा के लिए नोटिस को स्वीकार न करना था।

दूसरी ओर, सरकार का कानून बनाने की उत्पादकता के मामले में प्रदर्शन पर जोर संसद की प्रभावशीलता का बैरोमीटर बन गया। जबकि संसद के दोनों सदन देश के लिए कानून बनाने के लिए एकमात्र स्थान बने हुए हैं, सत्तारूढ़ गठबंधन के संसदीय प्रबंधकों की पर्याप्त जांच और बहस के बिना पारित होने की प्रवृत्ति विपक्ष के साथ विवाद का विषय बन गई है। अपनी अधिक संख्या की उपस्थिति ने सरकार को इस कहावत के उत्तरार्द्ध का पालन करने की अनुमति दी कि श्विपक्ष अपनी बात कह सकता है, सरकार अपना काम करेगी।

प्रस्तावित कानून को अधिकार क्षेत्र की समितियों द्वारा जांच के रूप में संसदीय निगरानी के अधीन करने का मानदंड दुर्लभ हो गया। तीन दशक पहले, संसद ने समिति प्रणाली का विस्तार करने का फैसला किया और विधेयकों को पढ़ने की एक अतिरिक्त परत शुरू की। इसने संसद की अच्छी सेवा की, जिससे सदन के सदस्यों को विधेयकों पर गैर-पक्षपातपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से विचार-विमर्श करने और प्रस्तावित कानून को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें देने की अनुमति मिली। समिति की बैठकों को सार्वजनिक चकाचौंध से दूर आयोजित करने या विचार-विमर्श के दौरान मीडिया तक पहुँच प्रदान करने का औचित्य सदस्यों की पार्टी लाइन पर दिखावा करने की प्रवृत्ति को रोकना था। सर्वसम्मति ही मंत्र था।

समितियाँ मुद्दों की जाँच करने और डोमेन विशेषज्ञों से सुझाव सुनने में बहुत सारा काम कर रही हैं जो अध्ययन के तहत किसी विषय पर सिफारिशें करने में अभिन्न अंग बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, विपक्ष ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों का हवाला दिया जिन्हें समिति को भेजे बिना ही मंजूरी दे दी गई, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए और अंततः सरकार को उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

विपक्ष का तर्क था कि अधिकार क्षेत्र की समिति द्वारा जांच और उसकी परामर्श प्रक्रिया से सरकार को एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त होता। यह अवसर चूक गया। संसदीय निगरानी की प्रणाली को विधेयकों को सार्वजनिक डोमेन में रखने और सुझाव आमंत्रित करने के बराबर नहीं माना जा सकता, जिन्हें बाद में नौकरशाही प्रक्रियाओं द्वारा जांचा जाता है। समिति का काम तब शुरू होता है जब संबंधित मंत्रालय विधेयक का मसौदा तैयार करता है, जिसमें यदि आवश्यक हो तो जनता से आने वाले सुझावों को शामिल किया जाता है।

दोनों सदनों के अलग-अलग प्रक्रिया और आचरण नियम हैं। इनका सावधानीपूर्वक पालन अपेक्षित है, लेकिन संसद भी समय-सम्मानित परंपराओं के अनुसार काम करती है। उदाहरण के लिए, जब मंत्री राज्यसभा में किसी मुद्दे पर स्वप्रेरणा से बयान देते हैं, तो सभापति सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दे सकते हैं, यह परंपरा सदन के लिए अद्वितीय है।

जबकि कई लोग अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की तर्ज पर चुनावों के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बीच बहस की आवश्यकता की वकालत करते हैं, दिन के निर्वाचित सरकार को प्रश्नकाल के दौरान हर दिन आयोजित करने की अनूठी प्रथा चल रही है। मंत्री सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होकर आते हैं, जो सूचना चाहने वालों की विषय की समझ की सीमा और उत्तर देने के लिए बाध्य व्यक्ति को दर्शाता है। कैलेंडर की अनुसूची प्रधानमंत्री कार्यालय सहित विशिष्ट दिनों में मंत्रालयों को आवंटित करती है। पिछले 10 वर्षों में, प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप नहीं किया है, जबकि एक कनिष्ठ मंत्री ने जवाब दिया है। एक और प्रथा जो चलन में है वह यह है कि प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्राओं के बाद एक बयान देते हैं, यह कार्य कभी-कभी विदेश मंत्री को सौंप दिया जाता है।

अध्यक्ष का पद:

संसद में सत्तारूढ़ गठबंधन और संयुक्त विपक्ष की पहली परीक्षा तब होगी जब नई लोकसभा के सांसदों को सदन के अध्यक्ष और संरक्षक का चुनाव करने के लिए बुलाया जाएगा। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास अपने व्यक्ति को रखने के लिए पर्याप्त संख्या है, भले ही विपक्ष पानी की जांच करना चाहे। हालांकि, दूसरा परीक्षण उपसभापति के चुनाव पर होगा, जो एक संवैधानिक पद है जो 17 वीं लोकसभा के पांच साल के कार्यकाल के दौरान खाली रहा। परंपरा और परंपरा का हवाला देते हुए, विपक्ष को उम्मीद है कि मौजूदा सदन में उसे यह पद दिया जाएगा। पिछले चार दशकों के दौरान, ऐसे अपवाद रहे हैं जब सरकार से बाहर की पार्टी का कोई सदस्य चुना गया। 1985 में और फिर 2014 में, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम के एम। थंबीदुरई ने यह सम्मान हासिल किया।

कार्यवाही के लिए, नया सत्र विपक्ष को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा, जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष दिए जाने वाले अभिभाषण के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली बहस विपक्ष को चिंता के मुद्दों को उठाने और उनका विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करती है, बिना इस बात से विचलित हुए कि विषय प्रासंगिक है। एक तरह से, प्रस्ताव को एक सर्वव्यापी संकल्प के रूप में देखा जा सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें आम सहमति बनाने पर जोर दिया गया और सुझाव दिया गया कि विपक्ष को एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक विरोधी के रूप में।

घर्षण के बिंदु:

नई लोकसभा के उद्घाटन सत्र से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच दो मौकों पर टकराव के मुद्दे उभरे। कांग्रेस ने महात्मा गांधी और बीआर अंबेडकर की मूर्तियों को संसद परिसर के भीतर श्रेरणा स्थल (या प्रेरणा स्थल) नामक एक नवनिर्मित और निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित करने के तरीके और भाजपा के भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के फैसले पर आपत्ति जताई।

पहला निर्णय, जैसा कि उसने तर्क दिया, संसद में स्थापित उचित प्रक्रिया के बिना लिया गया था, जबकि प्रोटेम स्पीकर पर दूसरे निर्णय में उस परंपरा की अनदेखी की गई जिसके अनुसार नए सांसदों के शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मौजूदा सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों को नियुक्त किया जाना चाहिए था। अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले निर्णय को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विचार-विमर्श किया गया था और श्इस पर राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे मामले में

संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजजू ने नियुक्ति का राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस की सार्वजनिक रूप से आलोचना की।

इससे पहले, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे से मुलाकात करके संसदीय कार्य मंत्री ने संकेत दिया कि संसदीय लोकतंत्र में, सत्तारूढ़ गठबंधन पुरानी परंपराओं का पालन करेगा। जैसे-जैसे दिन बीतते जाएंगे और नियमित सत्र शुरू होंगे, समायोजन की भावना को रेखांकित करने के लिए भूमिका में निपुणता की आवश्यकता होगी। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन को हर तरह की राय को साथ लेकर चलने में सबसे आगे रहना चाहिए, विपक्ष को संसदीय साधनों का सहारा लेकर सर्वश्रेष्ठ परिणाम निकालने के लिए अपनी रणनीति को फिर से जांचना होगा। और, बहस में शिष्टाचार बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी पक्षों पर होगी।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न: 18वीं लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इस लोकसभा में विपक्ष के नेता को दर्जा दिया जा सकेगा।
2. इस लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर सर्वाधिक बार के सांसद भर्तृहरि महताब को बनाया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the 18th Lok Sabha-

1. The leader of the opposition can be given the status in this Lok Sabha.
2. Most serving MP Bharti Hari Mahtab has been made the Protem Speaker of this Lok Sabha.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : A

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: नई लोकसभा में संख्या बल की बदली स्थिति किस प्रकार पिछली दो लोकसभाओं की तुलना में अधिक उत्पादक सत्र को सुनिश्चित कर सकेगा? चर्चा कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में नई लोकसभा में संख्या बल की बदली स्थिति की चर्चा कीजिए।
- दूसरे भाग में पिछली दो लोकसभाओं की तुलना में अधिक उत्पादक सत्र कैसे हो सकेगा, इस संदर्भ में चर्चा कीजिए।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।